(d) Various storages under construction in the basin would create a live storage capacity of 17 billion cubic metre and storages under consideration would add another 29.5 billion cubic metre of live storage in the basin. The National perspective for Water Resources Development formulated by the Ministry of Water Resources has a Himalayan River Development Component which envisages construction of storage reservoirs in Ganga basin for transfer of water from surplus to deficit areas. The National Water Development Agency is carrying out studies in this regard.

Erosion of River Ganga and Padma

2588. SHRI NILOTPAL BASU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Governments are aware of the recommendations of the expert Committee going into the problem relating to erosion of the river Ganga and Padma;

(b) if so, the details thereof and the reaction thereon; and

(c) what is Government's reaction to the demand of the Chief Minister of West Bengal on 8th May, 1998 for release of Rs. 139.50 crores in a phased manner in the first four years of the 9th Plan and the construction of two long spurs at 28th and 29th Km. upstream of Farakka Barrage in the Central sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes Sir,

(b) An Expert's Committee constituted by the Planning Commission has recommended short term measures costing Rs. 315 crore and long term measures costing Rs. 612 crores for tackling the problem of erosion in various reaches lying upstream and downstream of the Farakka Barrage in the districts of Malda and Murshidabad in West Bengal. The long and short term measures were prioritised and the schemes were allocated between the Centre and the Government of West Bengal based on their respective jurisdiction for providing funds by Planning Commission.

(c) In response to the demand of the Chief-Minister of West Bengal, Planning Commission has decided to sanction an additional central assistance of Rs. thirty crore for the Annual Plan (1998-99) of the State of West Bengal to enable the State undertake few anticrosion schemes on priority. Construction of two spurs at 28 km. and 29 km. upstream of Farakka Barrage has been given priority under short term measures in the Expert's Committee's recommendations for providing funds by the Planning Commission in the Central Sector.

पश्चिमी बंगाल में पानी में संखिया का विद्यमान होना

2589. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के अनेक क्षेत्रों में भूमि में संखिया होने के कारण जल में संखिया के तत्व पाए गए हैं;

(ख) क्या इसमे अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और अनेक व्यक्ति बीमार हुए हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां। पश्चिम बंगाल के आठ जिलों अर्थात (1) मुर्शिदाबाद, (2) माल्दा (3) नादिया (4) उत्तर 24 परगना (5) दक्षिण 24 परगना (6) हावड़ा (7) हुगली और (8) वर्धमान के भूजल में 0.05 मि॰ग्रा॰/लीटर से अधिक संखिया की मात्रा पायी गयी है। संखिया की उत्पति भूवैज्ञानिक है।

(ख) संखिया संदूषण के कारण उत्पन्न बीमारियों से बहुत से लोग पीड़ित है। तथापि, केन्द्र सरकार संखिया संदूषण के प्रभाव के कारण हुई किसी मृत्यु का आंकड़ा नहीं रखती है।

(ग) संखिया संदूषण समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:—

(1) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग एवं वित्तीय समर्थन से निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृत किया है:

(i) 858.33 लाख रु० लागत की प्रथम चरण कार्रवाई योजना, जिसमें संखिया प्रभावित स्रोतों के स्थान एवं बड़े आकार के नलकूपों को पूरा कर लिया गया है तथा चार जल आपूर्ति स्कीमों को प्रारंभ किया गया है।

(ii) माल्दा जिले के लिए 8848 लाख रु० की अनुमानित लागत की सतही जल पर आधारित पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(iii) 232.84 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर दक्षिण 24 परगना में संखिया प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल पर आधारित एक पाइपयुक्त जल आपूर्ति स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(iv) 750 करोड़ रु० की कुल लागत पर एक भावी योजना तैयार करना, जिसमें संखिया संदूषण का सामना करने के लिए दीर्घावधि एवं अल्पावधि उपाय शामिल हैं। योजना की कुछ मुख्य विशेषताओं में नलकूपों को गहरा करके प्रतिस्थापित करना, तत्काल राहत के लिए नई पाइप वाली जल आपूर्ति योजनाएं, सुरक्षित सफाई के लिए कुंओं एवं वर्षा जल कृषि संरचनाओं का निर्माण करना, सतही जल पर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं की स्थापना एवं नए स्रोत स्थानों की स्थापना करना शामिल है।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक आरोग्य संस्थान ने संखिया प्रभावित क्षेत्रों में मरक विज्ञान (एपिडेमिथोलाजिकल) संबंधी अध्ययन प्रारंभ कर दिया है।

(3) ग्रामीण विकास विभाग को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निम्नलिखित है:—

(i) ट्रापिकल मेडिसिन स्कूल एवं अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और सार्वजनिक आरोग्य संस्थान द्वारा 10.82 लाख रु० लागत की एक परियोजना पर पश्चिम बंगाल के भूजल में संखिया प्रदूषण संबंधी उप मिशन परियोजना।

(ii) पश्चिम बंगाल के छः जिलों में 4.125 लाख रु० की परियोजना लागत पर संखिया संदूषण का अध्ययन।

(iii) 4.93 लाख रु० की परियोजना लागत पर पुराने आरतेनिक प्रभावित क्षेत्रों में विषाक्तता का आकलन करने के लिए मरक विज्ञान (एपिडेमिथोलोजिकल) अध्ययन संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजना को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता द्वारा अध्ययन किया गया है।

(iv) संखिया और अन्य रासायनिक प्रदूषकों के नियंत्रण संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 2.74 लाख रु० की परियोजना लागत पर अनुमोदित किया गया। इसका अध्ययन प्रेसीडेन्सी कॉलेज, कलकत्ता को सौंपा गया है।

(v) भारत सरकार द्वारा भूजल से संखिया हटाने के लिए कम लागत के फिल्टर साधन के विकास की 3.304 लाख रु० की लागत वाली परियोजना का अनुमोदन किया गया है। इसका अध्ययन राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर को सौंपा गया है।

(vi) भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के छः जिलों में भूजल में संखिया प्राप्ति के भूविज्ञान और भूरासायनिक अध्ययन 4.78 लाख रु० की लागत वाली परियोजना का अनुमोदन किया गया है। इसका अध्ययन केन्द्र कलकत्ता को सौंपा गया है।

Replenishable Ground Water Available in the Country

2590. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey about the quantity of replenishable ground water available in the country, state-wise;

(b) if so, the details thereof;

(c) the irrigation potential that can be treated by this ground water in the districts of Kutch and Panchmahal and in other states; and

(d) whether Government have taken any measures for the maximum utilisation and recharging of ground water in each state?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) Based on the assessment made by the Central Ground Water Board, the